Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding condition of Government schools in Delhi.-Laid

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र और दिल्ली के तमाम उन सरकारी विद्यालयों की घोर अव्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं जहां जर्जर भवनों में क्षमता से अधिक बच्चे बैठाए जा रहे हैं । ऐसे कई विद्यालयों में मैं स्वयं गया जहां व्यवस्था के नाम पर घोर अव्यवस्था पाई गई, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के नाम पर विद्यालयों की व्यवस्था कारागार जैसी है जहां कहीं खुले आसमान के नीचे तो कहीं टीम सेट में अनियमित रूप से बच्चों की भारी भीड़ को बैठाया जाता है और हर दिन हर पल बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल कर अपने बेहतर भविष्य और शिक्षा की आस में पढ़ने को मजबूर है । कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना बच्चों की जान को खतरे में डाल सकती है । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा ऐसे कई विद्यालयों को नोटिस देकर रिपोर्ट भी तलब की गई है और कार्यवाई करने का आदेश भी दिया गया है लेकिन उचित कार्रवाई दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं की गई है । अतः मैं नियम 377 के अधीन माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कमेटी बनाकर दिल्ली के बदहाल स्कूलों की व्यवस्था की जांच कराई जाए और दोषी लोगों की जिम्मेदारी तय की जाए । साथ ही माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि केंद्रीय सहायता से दिल्ली में नए विद्यालय बनाए जायें जिससे बच्चों को अच्छी और सुरक्षित शिक्षा मिल सके ।